हिन्दी मासिक पत्रिका

देश-प्रदेश की सियासत पर पैनी नजर

सियासतगाह

पंजीयन क्रमांक : CHHHIN/2020/79297 मई 2021 www.siyasatgah.com

25/-

सेंट्रल विस्टा पर सियासी संग्राम

टीएस सिंहदेव बोले

Teeka App

अभी बच्चा है

छत्तीसगढ़ पहुँची सेंट्रल विस्टा पर सियासत

350 करोड़ से ज्यादा के निर्माण ठेके निरस्त

देश-प्रदेश की सियासत पर पैनी नजर
सियासतगाह
वर्ष-01, अंक-11

इंडेक्स

संपादक
वर्षा द्विवेदी

प्रबंध संपादक
गंगेश द्विवेदी

जिला ब्यूरो

आदेश श्रीवास्तव
राजनांदगांव

ऋषभ तिवारी
रायगढ़

झानू नागेश
धमतरी

शिव कुमार चौरसिया
बलरामपुर

अजय केडिया
अम्बिकापुर

रेखेन्द्र तिवारी
बिलासपुर

घनश्याम यादव
गरियाबंद

रजिस्टर्ड कार्यालय
हाउस नं.- जे 680 जनता कॉलोनी,
गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.)
पिन नं. 492009

स्वामी/मुद्रक एवं प्रकाशक वर्षा द्विवेदी द्वारा
मिशन मीडिया प्रा.लि. प्रेस काम्प्लेक्स,
रजबंधा मैदान,रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित
एवं हाउस नं.-जे 680, जनता कॉलोनी, गुढ़ियारी
रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित

RNI NO. CHHHIN/2020/79297
फोन : 0771 4270143
website : www.siyasatgah.com
Email : siyasatgah@gmail.com

(समस्त न्यायालयीन प्रकरणों के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र रायपुर होगा।)

02| सेंट्रल विस्टा पर सियासी संग्राम

05| छत्तीसगढ़ पहुँची सेंट्रल विस्टा पर...

08| टीका का आरक्षण या पॉलीटिकल...

10| छत्तीसगढ़ में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

12| कोरोना मरीजों पर ब्लैक फंगस...

13| दूसरी लहर में तीन गुना संक्रमण

19| सीजी टीका एप ठप

* समाचार लेख और आलेख को लेकर ये जरूरी नहीं है कि उससे संपादक सहमत हो। ये लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं।

कवर स्टोरी

सेंट्रल विस्टा पर सियासी संग्राम

वर्षा द्विवेदी
Email : editorsiyasatgah@gmail.com
+ 91 9907081788

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कांग्रेस-भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप तेज

कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मांग की जा रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस इस परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया गया। हालांकि, अदालत ने यह तो माना कि स्थिति असल में गंभीर है लेकिन याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगर वह इस जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट पर याचिका लगाई गई जिस पर सोमवार 17 मई को सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन इस पर चल रही सियासत तेज हो गई है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाया तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पलटवार किया है।

सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के आवास के साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है। एक केंद्रीय सचिवालय का भी निमाज़्ण किया जाएगा। इसके साथ ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक तीन किलोमीटर लंबे 'राजपथ' में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इनके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्थित 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

कला केंद्र' को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभागों के लिए कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया–सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह याचिका किसी न किसी की कमी को छिपाने के लिए डाली गई है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि उनके तर्क और बहस अप्रैल की अधिसूचना के आधार पर होंगे। तुषार मेहता के बाद शापूरजी पालोनजी ग्रुप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को निलंबित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका का विरोध किया। उनका कहना है कि यह कोई वास्तविक याचिका नहीं है। वहीं याचिका डालने वाले वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा नहीं कहना चाहिए बल्कि इसे अब 'मौत का केंद्रीय किला' कहा जाएगा। उन्होंने अदालत से इसपर जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके बावजूद सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम चल रहा है, ऐसे में मजदूरों और अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। जितनी जल्दी हो सके इस निर्माण कार्य को रोक दिया जाए।

परियोजना पैसों की आपराधिक बर्बादी– राहुल गांधी : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि लोगों की जान केंद्र में रखिए, न कि नया घर पाने के लिए अपनी अंधी हेकड़ी। वहीं, इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मामले में पार्टी का रुख अजीब है क्योंकि उसके नेताओं ने यूपीए सरकार के दौरान इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने संसद के नए भवन की जरूरत को

20 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट

दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 में पांच प्लॉटों के लिए लैंड यूज में संशोधन किया गया है जिसमें मौजूदा संसद के बगल में नया संसद भवन और प्रधानमंत्री के लिए नया आवास बनाने का प्रस्ताव शामिल है.

जहां एक तरफ पूरा भारत (और दुनिया) कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिशें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने महत्वाकांक्षी और विवादित- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट- के लिए दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है।

इस हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट का बजट 20,000 करोड़ रुपये का है. एक महामारी से लड़ते हुए पूरे भारत के लॉकडाउन में चले जाने के बावजूद इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करना ये दर्शाता है कि आखिर मोदी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक चार स्क्वायर किमी. क्षेत्र में स्थित कई ऐतिहासिक इमारतों का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास किया जाएगा. पांच प्लॉटों के लिए लैंड यूज में संशोधन किया गया है जिसमें मौजूदा संसद के बगल में नया संसद भवन और प्रधानमंत्री के लिए नया आवास बनाने का प्रस्ताव शामिल है। बीते 20 मार्च को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान और जोन-डी एवं जोन-सी के जोनल डेवलपमेंट प्लान (इंडिया गेट के बाहरी क्षेत्र पर प्लॉट नंबर 08 के लिए) में प्रस्तावित संशोधनों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में 1,292 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए और डीडीए द्वारा गठित बोडज़ ऑफइंक्वायरी एंड हियरिंग द्वारा इस पर विचार किया गया. इसके बाद केंद्र ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 और जोनल डेवलपमेंट प्लान में संशोधन करने का निणज़्य लिया और नोटिफिकेशन जारी कर अब इसकी पुष्टि कर दी गई है।

प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली मास्टर प्लान के लैंड यूज में बदलाव

नोटिफिकेशन के अनुसार नया संसद भवन एक त्रिकोणीय भूखंड पर आएगा, जिसे मौजूदा संसद के विपरीत प्लॉट नंबर 2 पर निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है. यह 9.5 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला होगा। पहले इस जगह को 'जिला पार्क' के लिए आवंटित किया गया था। संयोग से पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 75 वें वर्षगांठ के मौके पर 2022 तक में एक नए संसद के निर्माण की बात की थी। इससे पहले साल 2015 में तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर एक नया संसद भवन बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा इमारत की हालत ठीक नहीं है और यह कर्मचारियों, सुरक्षा, मीडिया आगंतुक और संसदीय गतिविधियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। संसद भवन को ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था और इसका निमाज़्ण 1921 में शुरू होने के छह साल बाद पूरा हुआ था. इस इमारत में आजादी से पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था. राहुल गांधी ने कहा- महामारी के दौर में सेंट्रल विस्टा नहीं दूरदर्शी सरकार जरूरी है।

लेकर चिट्ठियां लिखी थी। ट्वीटर में राहुल ने महामारी के दौरान लोगों से एक दूसरे की मदद की अपील करते हुए कहा कि इस 'अंधे सिस्टम' को सच दिखाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के दौरान भी सेंट्रल विस्टा का कार्य जारी रखने और सरकारी मदद से बनी वैक्सीन महंगे दामों पर बेचे जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। बुधवार को तीन ट्वीट करते हुए राहुल ने कहा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है, बल्कि एक दूरदर्शिता वाली केंद्र सरकार जरूरी है। सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत लाकर काम जारी रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, लेकिन मजदूरों के लिए विशेष बसें चलाई जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार नई संसद, पीएमओ और अन्य मंत्रालयों के भवन वाला सेंट्रल विस्टा 2023 तक तैयार हो जाना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में राहुल ने महामारी के दौरान लोगों से एक दूसरे की मदद की अपील करते हुए कहा कि इस 'अंधे सिस्टम' को सच दिखाया जाना चाहिए।

कवर स्टोरी

छत्तीसगढ़ पहुँची सेंट्रल विस्टा पर सियासत

350 करोड़ से ज्यादा के निर्माण ठेके निरस्त

मुख्यमंत्री ने नया रायपुर में सीएम हाउस, विधानसभा भवन सहित सभी निर्माण कार्य पर लगाई रोक

नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा पर राजनीति की आंच अब छत्तीसगढ़ पहुंच गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने प्रदेश में बन रहे नए विधानसभा भवन के निर्माण कार्य में रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते यह जानकारी दी. इससे पहले केंद्र सरकार दिल्ली में विस्टा प्रोजेक्ट के काम का बचाव छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्माण कार्य का हवाला देकर कर रही थी।

राज्य सरकार ने विधानसभा भवन के साथ साथ राजभवन, मुख्यमंत्री निवास और दूसरे अन्य निमार्णाधीन कार्यों पर रोक लगा दी है जिसके तहत जिसके तहत राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के घर बनाए जा रहे थे. सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा- हमारे नागरिक हमारी प्राथमिकता. उन्होंने आगे लिखा कोरोना काल से पहले प्रदेश में नए विधानसभा भवन, नए राजभवन, मुख्यमंत्री निवास के साथ-साथ प्रदेश के मंत्रीगण और सीनियर अधिकारियों के आवास बनाने का काम शुरू हुआ था. प्रदेश अभी कोरोना के बुरे संकट के दौर से गुजर रहा है इसलिए इन सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने का दबाव बढ़ सकता है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा नवा रायपुर में निर्माणाधीन नये राजभवन, नये सीएम हाउस, मंत्रीगणों व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नये सर्किट हाउस के निर्माण कार्यों में तत्काल प्रभाव से रोक के लिए संबंधित ठेकेदारों को आदेश जारी किया गया है।

इसके साथ ही सेक्टर-19 में नवीन विधानसभा भवन के निर्माण के लिए 245 करोड़ 16 लाख और 118 करोड़ के कार्यों की पूर्व में जारी निविदाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

राजनांदगांव सांसद ने लिखा भूपेश को पत्र : राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पांडेय ने सेंट्रल विस्टा और मोदी सरकार

की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा नया भारत बना रही है, जबकि भूपेश बघेल की प्राथमिकता सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित है। पांडेय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय जिस परियोजना की रूपरेखा बनी, उसे बदनाम करने की कोशिश में नया रायपुर के कुछ प्रोजेक्ट्स बंद करने की घोषणा करके सस्ती राजनीति कर रहे हैं। सांसद पांडेय ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिये केंद्र सरकार सालाना एक हजार करोड़ रुपये बचाने जा रही है। कई मंत्रालयों के कामकाज किराए की बिल्डिंग में अलग-अलग स्थान पर चल रहे हैं। पांडेय ने कहा कि आप कह रहे हैं सेंट्रल विस्टा बंद करिए। जानते हैं, देश के विकास के लिए अलग-अलग राज्यों में 13 ऐतिहासिक परियोजनाएं चल रहीं हैं।। क्या नर्मदा वैली प्रोजेक्ट को बंद कर दें। भारतमाला प्रोजेक्ट को बंद कर दें, क्योंकि महामारी है? दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रिवर रेलवे ब्रिज बंद कर दें? क्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल 1500 किमी कारीडोर बंद कर दें? क्या इनलैंड वाटर वेज पर काम चल रहा है, उसको बंद कर दें? क्या देशभर में स्मार्टसिटीज बन रही है, उन कामों को रोक देना चाहिए?

सागरमाला परियोजना सात लाख 78 हजार करोड़ की है। भारतमाला प्रोजेक्ट पांच लाख 35 हजार करोड़ का है, जिसमें 34 हजार 800 किलोमीटर सडकें बननी है। अरुणाचल प्रदेश को रेलवे मैप पर लाया जा रहा है। गुजरात

संतोष पांडे एक्सीडेंटल सांसद : आरपी सिंह

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता आर पी सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 4 पन्नों का सतही राजनैतिक पत्र लिखकर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने यह साबित कर दिया है कि वे एक एक्सीडेंटल सांसद है! उनका सांसद चुनाव लड़ना और पुलवामा की लहर में चुनाव जीत जाना महज एक संयोग था। उनके इस पत्र से एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि उनके अंदर एक अच्छे कवि और कथावाचक के गुण जरूर है लेकिन अच्छे सांसद के गुण भी हैं ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है। एक पुरानी कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए इस पत्र से यह साबित हो गया है की संतोष पांडे की योग्यता और राजनीतिक जानकारी कितनी है? कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने पत्र में उठाए हुए सभी प्रश्नों का जवाब सिलसिलेवार देते हुए कहा है कि संतोष पांडे को यह ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र है वहां की संसद भवनों में सबसे नवीनतम संसद भवन भारत का है। जिसका निर्माण सन 1923 में हुआ था। जब इससे पुरानी संसद भवन वाले देशों को नए भवन की आवश्यकता नहीं पड़ी तो फिर हमारे ही देश को नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? ऐसे समय में जब पूरा देश कोविड-19 की महामारी से लड़ रहा है। विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले मोदी को बांग्लादेश, भूटान ,नेपाल और पाकिस्तान जैसे छोटे-छोटे देशों से मदद देने की आवश्यकता पड़ रही है। तब 20 हजार करोड रुपए का सेंट्रल विस्टा उर्फमोदी महल प्रोजेक्ट बनाकर जनता के खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने की क्या आवश्यकता थी? 70 सालों में कई पार्टियों की सरकार केंद्र में आई बहुत सारे प्रधानमंत्री भी हुए लेकिन क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपने लिए 8500 करोड़ रुपये का उड़न खटोला खरीदा? दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की विफलता ढोल जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बज रहा हो। और पूरी दुनिया मोदी की विफलता के मिसालें दे रहा हो तब प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए संतोष पांडे ने यह पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है।

से गोरखपुर तक की 1987 किमी की पाइप लाइन को बनाया गया। चार धाम हाइवे प्रोजेक्ट उसको भी सरकार बना रही है। क्या इन सबको आपकी राजनीति की भेंट चढ़ा दी जाए? पांडेय ने कहा कि भूपेश जी, हमारे नागरिक हमारी प्राथमिकता हैं। आपकी प्राथमिकता बस नकली गांधी परिवार। हमारे लिए देश ही अपना परिवार है, आपके लिए परिवार ही देश। एक परिवार का हितपोषण कर ही आप अपने नियुक्त होने का कर्ज चुकाना मान लेते हैं, यही फर्क है आपमें और किसी देशभक्त में। काश आपको पता होता कि सेंट्रल विस्टा को लेकर अलग-अलग अदालतों में लंबी बहस पहले ही हो चुकी है। बाकायदा वैध तरीके से सारे कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए वहां कार्य हो रहे हैं।

नहीं चलेगा भूपेश माडल, असम ने भी ठुकराया : पांडेय ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी ही राजनीति का परिणाम है कि आधी सदी तक देश पर शासन करने वाली आपकी पार्टी को दो बार से जनता ने केंद्र में विपक्ष के लायक भी नहीं रहने दिया है। पार्टी अब देश के महज तीन राज्यों में सिमट गई है। असम में सपना पाले थे, केरल में भी देख रहे थे, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस तो स्वयं समापन की ओर है। छत्तीसगढ़ में भी अब भूपेश माडल नहीं चलेगा।

केजरीवाल की तरह बनना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुख्यमंत्री : भूपेश जी, प्रदेश ने आपके वादों पर भरोसा करके आपको बागडोर सौंपा, लेकिन आपको दिल्ली-असम से ही फुर्सत नहीं। सीएम पद को केवल निजी लाभ का जरिया बनाकर आप केजरीवाल की तरह ही अंतरराष्ट्रीय मुख्यमंत्री की होड़ में हैं।

नवा रायपुर के निर्माण रद्द, अब मोदी सरकार भी प्रोजेक्ट रद्द करे: सुशील शुक्ल

केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से सीख ले कर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रद्द करे। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नए रायपुर के निर्माण कार्यों को रद्द करने का निर्णय ले कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के संकट के समय अपनी प्राथमिकता बता दी कि उनके लिए राज्य की जनता के लिए स्वास्थ सुविधा जुटाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मिव्ययता बरतते हुए नए रायपुर के निर्माण कार्यों को रद्द कर दिया। नए रायपुर में सीएम हाउस, राजभवन मंत्रियों के निवास का भूमिपूजन कोरोना काल के पहले हो गया था । केंद्र सरकार ने 20000 करोड़ की लागत के सेंट्रल विस्टा का भूमिपूजन कोरोना के मध्य में किया है। सेंट्रल विस्टा निर्माण को देश भर की जनता द्वारा कोरोना संकट में फिजूल खर्ची बताए जाने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ के निमाज़्ण कार्यों पर सवाल खड़ा किया था जबकि दोनों की तुलना अनुचित थी अब नड्डा में साहस हो तो वे मोदी से कहे कि केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रद्द करें। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सेंट्रल विस्टा की लागत बीस हजार करोड़ रुपए से देश की तीन चौथाई आबादी का वेक्सिनेशन हो जाएगा देश भर में हजारों सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बन जायेगे। सेंट्रल विस्टा मोदी की विलासिता पूर्ण मनोस्थिति और शाहखची का प्रतिबिंब है जो हजारो करोड़ के प्रधानमंत्री आवास में रहने का सपना देख रहे और जिसको पूरा करने के लिए वे देश को दवाई ऑक्सिजन और वैक्सीन से ज्यादा प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा के निर्माण को दे रहे है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच मे जब वैक्सीन और अस्पतालों दवाइयों के लिये योजना बनाने की जरूरत थी मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा की योजना बना उसको मूर्त रूप देने के लिए कवायद कर रही थी ।

कवर स्टोरी-3

टीका का आरक्षण या पॉलीटिकल ड्रामा

सरकार ने शपथपत्र असिस्टेंट प्रोफेसर से पेश करा दिया, कोर्ट की नाराजगी के बाद मांगा समय, सुनवाई 4 जून को

छत्तीसगढ़ में 18+ को टीका : वैक्सीनेशन के लिए सामाजिक-आर्थिक आधार पर प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ में टीका का आरक्षण करने के बाद से पॉलीटिकल ड्रामा लगातार जारी है। मामला कोर्ट में पहुंच गया है, बार-बार कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने में ढिलाई बरती जा रही है। 18+ वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पर शपथ पत्र दिया, कोर्ट के नाराजगी दिखाने पर अब शपथ पत्र दायर करने के लिए हाईकोर्ट से और समय मांगा है। इसके बाद कोर्टकी ओर से 4 जून तक का समय दिया गया है। साथ ही कोट ने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की अपनी-अपनी पॉलिसी है। उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन वैक्सीनेशन पर नजर रख सकते हैं। सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई।

शुक्रवार को हो रही सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा की वैक्सीनेशन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई पहलू हैं। टीकों की सप्लाई और कोल्ड स्टोरेज की समस्या भी शामिल है। इस टीकाकरण अभियान में राज्य सरकार और केंद्र की अपनी-अपनी पॉलिसी है। उस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, जिससे टीकाकरण प्रभावित हो जाए। हां हम वैक्सीनेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, उस पर नजर रख सकते हैं।

पहले शपथ पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से दिया, उसमें स्पष्ट जानकारी नहीं थी : दरअसल, कोर्ट ने अंत्योदय में बच रही वैक्सीन को दूसरे वर्ग के लिए शिफ्ट करने को कहा था। तब राज्य सरकार ने बताया था कि वह ऐसा कर रही है, जिसके बाद कोर्ट ने शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इस पर सरकार की ओर से 19 मई को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। यह असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से था। टीकों को लेकर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था और पॉलिसी ड्राफ्ट व एफिडेविट में भी अंतर था। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी।

शासन की ओर से कहा गया था- चीफ सेक्रेटरी के नाम से करा देंगे : कोर्ट की नाराजगी पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अगर कहेंगे तो चीफ सेक्रेटरी के नाम से शपथ पत्र पेश करा देंगे। वहीं कोर्ट ने शपथ पत्र की कॉपी न्यायमित्र को नहीं मिलने पर दो दिन बाद जवाब मांगा था। इस मामले में ही शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। जिसके बाद सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांग लिया गया। हालांकि मामले की अगली सुनवाई अब कब होगी, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है।

वैक्सीन की बर्बादी पर सख्त हुआ कोर्ट : छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट

ने वैक्सीन डोज की बबार्दी को लेकर नाराजगी जताई है। कहा कि सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है। ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी। वैक्सीन एक जगह बच रही है तो उसे अन्य वर्ग के लिए शिफ्ट करें। इस मामले में कोर्ट ने दो दिन में सरकार को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

इसलिए उलझा टीकाकरण और कोर्ट हुआ सख्त : राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को आदेश जारी कर एक मई से 18+ के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी। इस आदेश में कहा गया कि यह टीका सबसे पहले अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को लगेगा। उनको लग जाने के बाद बीपीएल परिवारों के 18 से 44 आयु वर्ग और सबसे अंत में एपीएल को टीका लगाया जाएगा। विपक्ष इसको आरक्षण बताकर विरोध कर रहा है। कोरोना संक्रमण मामले में स्व प्रेरणा से कोर्ट में चल रही सुनवाई में ही ये भी जनहित याचिकाएं लगाई गई हैं।

सरकार की ओर से कहा गया- बची वैक्सीन दूसरे वर्ग में शिफ्ट कर रहे : अधिवक्ता अनुमय श्रीवास्तव ने कहा, वैक्सीन बच जा रही है तो बाकी का क्या होगा उसका पता नहीं है। अंत्योदय में जो वैक्सीन बच जाती है, उसे दूसरे वर्ग के लिए शिफ्ट करें। जिससे बेकार न हो। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हम शिफ्ट कर देते हैं। वैक्सीन की बर्बादी को रोक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार को दो दिन में इस मामले और 9 पेज की नीति को लेकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

वैक्सीन पर रोक नहीं लगा सकती सरकार : इससे पहले हाईकार्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को वैक्सीनेशन स्थगित करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने साफकर दिया था कि सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी वर्ग को 33 प्रतिशत के हिसाब से सामान रूप से वैक्सीन लगाई जाए। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से दो दिन में स्पष्ट पॉलिसी बनाने को कहा था। इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दरअसल, राज्य सरकार ने 18+ के वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दी थी। इसके खिलाफ जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 मई को सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। इसमें कहा था कि बीमारी अमीर-गरीब देखकर नहीं आती है। इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती।

बीमारी अमीर-गरीब देखकर नहीं आती : हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन में गरीबों को प्राथमिकता देने वाले राज्य सरकार के फैसले पर सुनवाई के दौरान 4 मई को हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि बीमारी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं आती है। इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती।

हाईकोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव के आदेश को गलत बताते हुए एक स्पष्ट पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट में यह याचिका सरकार की ओर से वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्ड धारकों को प्राथमिकता देने के खिलाफ लगाई गई है। आरक्षण प्रणाली का यह निर्णय और आदेश संवैधानिक अधिकार के विपरीत है। आदेश कैबिनेट के निर्णय से होने चाहिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि 18 साल से ऊपर को वैक्सीन लगाने के लिए ष्ट्स् का आदेश गलत है। यह आदेश कैबिनेट के निणज़्य से होना था, न कि किसी अधिकारी द्वारा जारी किया जाना था। अफ्सर को यह अधिकार नहीं है कि ऐसे मामले में निर्णय ले। केंद्र सरकार के निर्णय से प्रतिकूल होकर राज्य ऐसे मामलों में निर्णय नहीं ले सकते, डब्ल्यूएचओ के नियम के विपरीत नहीं जा सकते हैं, न ही किसी वर्ग विशेष को संरक्षित कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

रायपुर सहित इन चार जिलों में लॉकडाउन में मिलेगी छूट मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को दी हालात के मुताबिक फैसले का अधिकार, बैठक के बाद लिया गया निर्णय

छत्तीसगढ़ में लॉक डॉउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया। यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 जिलों के चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से कोविड-19 के संबंध में चर्चा के दौरान लिया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव तथा बिलासपुर के कलेक्टर और व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू तथा मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री बघेल ने चर्चा के दौरान कहा कि राज्य में सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। इनमें व्यापार-व्यवसाय का भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा शासन की दिशा-निदेर्शों का शत-प्रतिशत पालन सहित संचालन की जरूरत है। जिससे लोगों को कोई असुविधा न होने पाए। उन्होंने इसके मद्देनजर संबंधित जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप अति आवश्यक दुकानों को अलग-अलग अवधि तथा समय में खोलने के लिए छूट देने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इनमें कहीं भी भीड़ एकत्र न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसी तरह वहां कोविड-19 के नियमों का भी नियमत: पालन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इसके लिए कलेक्टरों को चेम्बर ऑफकॉमर्स सहित सभी वर्ग के लोगों से चर्चा कर उन्हें विश्वास में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना संकट से निपटने में शासन-प्रशासन के साथ-साथ सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी रही है। यहां सबके सहयोग से कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश भर में लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस कड़ी में उन्होंने

पीएम की नाराजगी: कोरोना के मामले न छिपायें राज्य सरकार, वेंटीलेटर्स का उपयोग नहीं होने पर जताई चिंता : देश में जारी कोरोना के कहर को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विभिन्न मंत्रालय के मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए. प्रधानमंत्री ने कहा, स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के लिए रणनीति बनाया जाना जरूरी है, जहां तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा, जिन जगहों पर कोरोना के अधिक मामले हैं, वहां पर आरटी-पीसीआर और रैपिड टेस्ट तेजी से किया जाना चाहिए. पीएम मोदी ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का इस्तेमाल ना होने की खबरों को गंभीरत से लिया और उस पर नाराजगी जताई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक में कहा, वेंटिलेटर, अन्य उपकरणों के इस्तेमाल के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को जरूरी प्रशिक्षण देना चाहिए. प्रधानमंत्री ने बताया, मार्च की शुरुआत में हर सप्ताह करीब 50 लाख नमूनों की जांच हो रही थी, वहीं अब प्रति सप्ताह करीब 1.3 करोड़ नमूनों की जांच हो रही. पीएम ने कहा, संक्रमितों की संख्या में ज्यादा वृद्धि के बावजूद राज्यों को कोरोना के मामलों को बिना किसी दबाव के पारदर्शी तरीके से सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. पीएम ने कुछ राज्यों में भंडारण में अप्रयुक्त वेंटिलेटर के बारे में कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि केंद्र द्वारा प्रदान किए गए वेंटिलेटर की स्थापना और संचालन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए.

चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की बैठक ली। जिसमें व्यापारिक प्रतिनिधियों ने कोरोना नियंत्रण के लिए हर संभव मदद देने सहित दुकान आदि के संचालन के संबंध में आवश्यक सुझाव भी दिए। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री बघेल के निर्देशन में कोरोना नियंत्रण के लिए हर संभव उपाए किए जा रहे हैं, इसका अच्छा परिणाम भी दिख रहा है। इस दौरान हम सभी को सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि लॉकडाउन अभी खतम नहीं हुआ है। इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसी तरह वन मंत्री अकबर ने कहा कि अति आवश्यक दुकानों को ही सीमित अवधि के लिए अलग-अलग समय में छूट दी जानी चाहिए।

हिन्दी मासिक पत्रिका
देश-प्रदेश की सियासत पर पैनी नजर
सियासतगाह
आवश्यकता है
छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला, ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता एवं विज्ञापन प्रतिनिधियों की
संपर्क करें :- 8770567280, 8817688853

न्यूज़ स्टोरी व आलेख
प्रदेश स्तर पर राजनीति, शिक्षा, क्राइम, समाज से जुड़े अनेक विषयों पर मय सबूत न्यूज स्टोरी देने वाले हरफनमौला पत्रकारों से आमंत्रित है विशेष स्टोरीज प्रकाशित होने पर सामान्य स्टोरी के लिए 300 रुपये और बड़ी स्टोरी पर 500 रुपए प्रति स्टोरी।
हिन्दी मासिक पत्रिका
देश-प्रदेश की सियासत पर पैनी नजर
सियासतगाह

कोरोना मरीजों पर ब्लैक फंगस का काला साया

ब्लैक फंगस या म्यूको माइकोसिस इन दिनों कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में इसके 2 हजार से ज्यादा मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र में इससे अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में इसके मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं अब राजधानी दिल्ली में भी इसके मामले तेजी से सामने आने लगे हैं। दिल्ली के एम्स और सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के कुल 29 मरीज भर्ती हैं। आइए जानते हैं कि क्या है ब्लैक फंगस और ये किन लोगों को अधिक प्रभावित करता है।

ब्लैक फंगस म्यूकॉमाईसेट्स नामक मोल्ड्स के एक समूह के कारण होता है : जो पूरे प्राकृतिक वातावरण में पाए जाते हैं। यह अक्सर साइनस, फेफड़े, त्वचा और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो अन्य बीमारियों के लिए दवा ले रहे हैं। ये फंगस विशेष रूप से शुगर के मरीजों को अधिक प्रभावित करता है। पहले से किसी अन्य बीमारी के कारण दवा ले रहे मरीजों में पर्यावरणीय रोगजनकों से लड़ने की उनकी क्षमता कम होती है। ऐसे व्यक्तियों के साइनस या फेफड़े हवा के जरिए फंगल बीजाणुओं के अंदर जाने के बाद प्रभावित हो जाते हैं। इसके लक्षणों में मुख्यत: बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस फूलना, खून की उल्टी और बदली हुई मानसिक स्थिति शामिल हैं।

कोरोना मरीजों को ज्यादा प्रभावित क्यों कर रहा ब्लैक फंगस : जिन लोगों का शुगर कंट्रोल से बाहर होता है ऐसे कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का अधिक जोखिम होता है। ऐसे मरीजों का इलाज स्टेरॉयड के जरिए किया जाता है, जो आगे रोगप्रतिरोधक क्षमता से समझौता करता है। भारत में डॉक्टरों का मानना? है कि स्टेरॉयड जो गंभीर और गंभीर रूप से बीमार कोविड -19 रोगियों के लिए जीवन रक्षक उपचार के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं, म्यूकोमाइकोसिस के लिए ट्रिगर साबित हो सकते हैं। स्टेरॉयड फेफड़ों में सूजन को कम करने में मदद करते हैं, ये प्रतिरक्षा को कम कर सकते हैं और शुगर रोगियों और गैर-मधुमेह कोविड -19 रोगियों दोनों में समान रूप से ब्लग शुगर के स्तर को बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक आईसीयू में रहने वाले मरीजों को भी ब्लैक फंगस का खतरा अधिक होता है।

ब्लैक फंगस का शिकार होने से ऐसे बचें

- म्यूको माइकोसिस जैसे खतरनाक ब्लैक फंगस से बचने के लिए कोविड -19 रोगियों को नियमित रूप से अपनी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए।
- शुगर के मरीजों को भी अपने ब्लड शुगर के स्तर की निगरानी करनी चाहिए।
- वहीं डॉक्टरों को एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल और स्टेरॉयड का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।
- अस्पतालों को ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए स्वच्छ, स्टेराइल पानी का उपयोग करना चाहिए।
- धूल भरे निर्माण स्थलों पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए।

खास रपट...

दूसरी लहर में तीन गुना संक्रमण

दो महीने पहले केवल 3.17 लाख लोगों को हुआ था कोरोना, अब पॉजिटिव केस की संख्या 9 लाख के करीब पहुंची

छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है। शुक्रवार रात तक प्रदेश में 7 हजार 594 नए संक्रमित मरीज मिले। यह अप्रैल महीने में आ रहे मरीजों के करीब आधे हैं। पिछले महीने औसतन 15 हजार मरीज रोज मिल रहे थे। इनको मिलाकर प्रदेश में अब तक 8 लाख 99 हजार 925 लोगों को यह वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 7 लाख 72 हजार 500 लोग वायरस को मात दे चुके हैं। 10 हजार 908 लोगों को तो शुक्रवार को ही डिस्चार्ज किया गया। इनमें से भी 85 प्रतिशत लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 11 हजार 461 लोग इस महामारी की वजह से मारे गए। वहीं 1 लाख 15 हजार 964 लोग अभी भी इलाज करा रहे हैं।

इन आंकड़ों में खतरनाक यह है कि पिछले दो महीनों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या करीब तीन गुना हो गई है। दो महीने पहले यानी 15 मार्च 2021 को प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या 3 लाख 17 हजार 329 थी जो वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। उस दिन प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 4006 थी। इन दो महीनों में 5 लाख 82 हजार 596 नए मरीज सामने आ चुके। एक्टिव मरीजों की संख्या भी उस दिन से 1 लाख 11 हजार अधिक है। इन दो महीनों में 7 हजार 571 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। माना जाता है कि कोरोना की दूसरी लहर मार्च 2021 के पहले सप्ताह से शुरू हुई।

11 प्रतिशत तक पॉजिटिविटी रेट : छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की औसत पॉजिटिविटी दर घटते हुए 11 प्रतिशत तक पहुंच गई है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 63 हजार 94 सैम्पल जांचे गए। वहीं 7 हजार 594 नए संक्रमित मरीज मिले। इस मान से प्रत्येक 100 सैम्पल की जांच में केवल 12 लोग पॉजिटिव पाए गए। मई की शुरुआत में संक्रमितों की यह दर 28 प्रतिशत तक थी।

मौतें कुछ कम हुई, लेकिन हालात चिंताजनक : प्रदेश में 172 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। इनमें से 92 मरीजों को

कोरोना संक्रमण से पहले दूसरी गंभीर बीमारियां थीं। रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। मौतों की संख्या अप्रैल के आंकड़ों की तुलना में कम जरूर हुई हैं, लेकिन मरीजों की घटती संख्या के बीच यह हालात की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। गुरुवार को प्रदेश में 195 लोगों की जान गई थी। 8 मई तक तो मौतों की संख्या 200 से अधिक थी।

केवल 4 जिलों में नए मरीजों की संख्या 500 पार : अभी प्रदेश के 28 में से केवल 4 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण का शिकार हुए नए मरीजों की संख्या 500 को पार कर सकी है। शुक्रवार को सबसे अधिक 623 मरीज जांजगीर-चांपा में मिले। रायगढ़ में 571 मरीजों का पता चला। वहीं बलौदा बाजार में 532 और सूरजपुर जिले में 518 मरीज सामने आए हैं।

बेहतर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण और उपचार से छत्तीसगढ़ ने कोरोना पर कसी नकेल

राज्य में हर रोज प्रति दस लाख आबादी पर 2197 टेस्ट, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 1245

छत्तीसगढ़ राज्य बेहतर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण और उपचार से कोरोना पर नकेल कसने में कामयाब हुआ है। राज्य में हर रोज प्रति दस लाख आबादी पर 2197 टेस्ट किए जा रहे है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 1245 ही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सतत् मॉनिटंरिग और निर्देशन से अब 39 लैबों में ट्रूनाट और 15 में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा मुहैया करायी जा ही है। इसके साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बलौदाबजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर और कोरबा में 6 नये शासकीय लैब और तैयार हो रहे है। एंटिजन टेस्ट राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों स्तर तक उपलब्ध है जबकि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त मशीन प्रदाय कर ट्रूऩाअ लैब की जांच क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों से संक्रमण दर में तेज गिरावट आयी है, अप्रैल में जो संक्रमण दर 30 प्रतिशत के करीब थी वह उतरकर अब 12 प्रतिशत हो गई है। पिछले साल जहां कोविड संक्रमित मरीज पर औसत 4 से 4 कॉंटेक्ट्स को ही टेऊक्र किया जा रहा था वहीं अब हर कोविड मरीज के 7 संपर्कों की तलाश और उनकी जांच सुनिश्चित की जा रही है जिससे संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली है।

प्रदेश में वर्तमान में 1063 कॉंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किये गए हैं जहां घर-घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तथा कुल 154 कोविड केयर सेण्टर बनाए गए हैं इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भी बनाए गए है। शासकीय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 5294 बेड तथा कोविड केयर सेण्टर में 16405 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। निजी कोविड अस्पतालों में 9 हजार 596 बेड उपलब्ध कराए गए है। इसके साथ ही कुल 1151 वेटिंलेटर उपलब्ध कराए गए है जिसमें 526 शासकीय और 625 निजी अस्पतालों में है।

ऑक्सीजेनेटेड बेड की संख्या बढ़ाये के लिए राज्य में 18 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित किये गए हैं इसके अतिरिक्त 6 प्लांट्स प्रक्रियाधीन हैं इनमे से 3 प्लांट अगले एक सप्ताह में स्थापित हो जायेंगे। रायपुर मेडिकल कॉलेज में एक विशेष टेलीकंसल्टेशन हब स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से मई 2020 से कॉलेज के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक दिन सभी शासकीय डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित कर उन्हें टेलीकंसल्टेशन प्रदान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर टेली राउंड भी लिए जाते हैं।

डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में वर्चुअल ओ.पी.डी. की सुविधा : वर्तमान में सामान्य मरीजों की सुविधा के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में वर्चुअल ओ.पी.डी. की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। यह सुविधा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक उपलब्ध है। इस दौरान मेडिसिन विभाग, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग एवं मनोरोग विभाग के विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ने पर अन्य विभागों के चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे। लिंक के माध्यम से वर्चुअल ओ.पी.डी. ज्वाइन की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में अब तक 7.72 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं जिसमें से 1.38 लाख अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तथा 6.34 लाख मरीजों ने होम आइसोलेशन की अवधि पूरी की है। होम आइसोलेटेड मरीजों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में कण्ट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है।

18-44 वर्ष के आयु वर्ग के 3.99 लाख लोगों का टीकाकरण : बीते 11 मई को भारत सरकार की वीडियो कांफ्रेंसिंग के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु समूह को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज देने में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान पूरे देश में छठा है। पूरे देश में सिर्फ लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेशही छत्तीसगढ़ से आगे हैं। यदि हेल्थ केयर वर्कस की प्रथम डोज की कवरेज की बात करें तो छत्तीसगढ़ (98.4 प्रतिशत) के साथ देश में तीसरे नंबर पर है। प्रदेश में 2 अप्रैल 2021 को सर्वाधिक 3.26 लाख व्यक्तियों का तथा 3 अप्रैल को 2.92 लाख व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। 14 मई तक राज्य में कुल 64.20 लाख हितग्राहियों को वैक्सीन डोजेज दी गई हैं। 14 मई 2021 को 2,086 सेशन मे 40,266 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। 14 मई तक 18-44 वर्ष के आयु वर्ग वाले कुल 3,99,262 हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया। 14 मई 2021 के टीकाकरण के पश्चात् केंद्र सरकार के चैनल में से 2,72,050 डोज तथा राज्य सरकार के चैनल में से 96,950 शेष हैं।

सार्वजनिक स्थल पर मास्क नही लगाने वाले लोगों से 3.44 करोड़ रूपए की वसूली : 25 फरवरी 2021 से 10 मई 2021 तक सभी जिलों के 2.22 लाख लोगों से 3 करोड़ 44 लाख रुपये की वसूली की गई।

कलेक्टर के खिलाफ अधिकारी का धरना

विभाग में गड़बड़ी व कार्रवाई नहीं होने से खफा अफसर की गांधीगिरी से मचा हड़कंप, दो पेज के शिकायत में लगाये हैं कई गंभीर आरोप

महासमुंद में एक अफसर ने कलेक्टर डोमन सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ना सिर्फ मोर्चा बल्कि नाराज अफसर अब धरने पर बैठ गया है। पूरा मामला भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के मामले में कारज्वाई नहीं होने को लेकर है। महासमुंद के महिला बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले का आरोप है कि विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर उसने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा था, लेकिन कलेक्टर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दो पेज के कलेक्टर को संबोधित पत्र में सुधाकर ने लिखा है कि महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर रखते हुए उन्हें ज्यादा अधिकार नहीं है, लिहाजा वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।' सुधाकर बोदले ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और रेडी टू ईट वितरण योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। कन्यादान योजना के उपहार खरीदी में करीब 20 लाख और रेडी टू ईट योजना में 10 लाख का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसका जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया था, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

रेमने गोठान की स्व-सहायता समूह की महिलाएं गन्ने से अच्छी गुणवत्ता वाली गुड़ बनाकर बनी आत्मनिर्भर

जिला प्रशासन ने समूह को गन्ना पेराई करने के लिए मशीन भी उपलब्ध कराया,

महिलाएं अब तक 25000 रुपए तक के गुड़ बना ली है

गन्ना उत्पादन और गुड़ विक्रय से आर्थिक लाभ समूह को हो रहा है,

जशपुर जिले में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोठान से जुड़कर स्व-सहायता समूह की महिलाएं गोबर से खाद बनाने के साथ ही अन्य आजीविका से जुड़ी है। प्रथम चरण में स्वीकृत गोठान में महिलाएं अनेक गतिविधियों में शामिल होकर आत्मनिर्भर बन रही है। कलेक्टर महादेव कावरे के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ के एस मंडावी दिशा-निर्देश में ग्राम गेड़ई ग्राम पंचायत रेमने में स्व-सहायता समूह की महिलाएं गोबर खरीदी कर वरमी खाद उत्पादन के साथ गोठान को स्वावलंबी बना रही है ।

समूह की महिलाएं गोठान में गन्ना की खेती की है और अच्छी फसल का लाभ भी उन्हें मिल रहा है । गन्ने से अब महिलाएं गुड़ बनाने का भी कार्य कर रही है । गन्ने और गुड़ से उनको आर्थिक लाभ भी हो रहा है । जनपद सीईओ अनिल तिवारी ने बताया कि समूह को गन्ना पेराई के लिए जिला प्रशासन द्वारा मशीन निशुल्क उपलब्ध कराया गया है। समूह की महिलाओं ने लगभग 25000 हजार रुपए तक के गुड़ तैयार कर ली है । बाजार में गुड़ की अच्छी खासी मांग है।

उल्लेखनीय है कि जशपुर जिले में कुल स्वीकृत गोठान 210 है इनमें 189 गोठान के माध्यम से गोबर खरीदी की जा रही है ।

इनमें जशपुर विकास खंड में 23 मनोरा में 20 दुलदुला 13 कुनकुरी में 24 कांसाबेल 20 फरसाबहार में 29 पत्थलगांव में 42 और बगीचा में 34 और नगरीय निकाय में एक एक कुल 5 गोठान से गोबर खरीदी की गई है। कुल गोबर खरीदी किवंटल 93200.77 क्विंटल कुल उत्पादित वरमी खाद की मात्रा किवंटल में 2566.46 विक्रय की गई खाद की मात्रा क्विंटल में 2029.11 क्विंटल विक्रय की गई प्राप्त राशि 20.25 लाख वरमी टांका वरमी बेड लो कास्ट उपयोग किए गए गोबर की मात्रा क्विंटल में 55658.41 है। इसी प्रकार गोठान समिति को लाभांश राशि 10.003 लाख और स्व-सहायता समूह को लाभ 1.765 लाख शामिल हैं।

गौठान से बढ़ गई आमदनी

घर खर्च चलाने में हो रही आसानी

कोरोना काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बना गौठान

स्व-सहायता समूह की महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर

पहले अपने ही गांव में बेराजगार रहने वाली अनेक महिलाओं को अब गौठान के माध्यम से रोजगार मिल गया है। महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर गौठानों का बखूबी संचालन ही नहीं कर रही है, अपितु अपने आमदनी का जरिया भी बना चुकी है। कोरोना संक्रमण काल से जहां अनेक व्यापार व व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, वही ग्राम सुराजी योजना के तहत् निर्मित गौठानों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं आमदनी अर्जित कर घर का खर्च भी उठा रही है।

उत्तर बस्तर कांकेर की स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न आर्थिक गतिविधियां जैसे- वर्मीकंपोस्ट उत्पादन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन इत्यादि कार्य कर आमदनी प्राप्त की जा रही है। यहां चारामा विकासखण्ड के आंवरी गोठान में वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन, मुगी पालन, सब्जी उत्पादन, मक्का एवं अरहर तथा मशरूम उत्पादन कर स्व-सहायता समूह की महिलायें आसपास के गांवो में मुर्गी तथा सब्जी बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। शासन की ग्राम सुराजी योजना के तहत निर्मित आंवरी गौठान स्थानीय स्वसहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिलाने के साथ उनको आमदनी भी उपलब्ध करा रही है।

जिला पंचायत कांकेर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने बताया कि कोराना संक्रमण के इस दौर में राज्य शासन की ग्राम सुराजी योजना के तहत् नरूवा, गरूवा, घुरूवा व बाड़ी ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। चारामा विकासखण्ड के ग्राम आंवरी गौठान की गुरू घासीदास महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 33 हजार रूपये का वर्मी विक्रय किया गया है। इसी प्रकार जय अम्बे स्व-सहायता समूह की महिलायें बिहान योजना के तहत बैंक लिंकेज व पशु विभाग के अभिसरण से कड़कनाथ मुर्गी पालन का कार्य कर रही है, उनके द्वारा 01 लाख 22 हजार 500 रूपये का मुर्गी विक्रय किया गया है। जय सफुरा माता समूह के द्वारा सब्जी, मक्का व अरहर उत्पादन कर 01 लाख 32 हजार का सब्जी विक्रय किया गया है।

इस प्रकार आंवरी गौठान में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा वर्मी कम्पोस्ट, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, मक्का एवं अरहर व मशरूम उत्पादन कर 02 लाख 96 हजार 500 रूपये में विक्रय किया गया, जिसमे उन्हे 02 लाख रूपये की शुद्ध आमदनी हुई। गौठान में काम करने वाली प्रति महिला सदस्यों को 8 से 10 हजार रूपये का फायदा हुआ है। सीईओ डॉ कन्नौजे ने बताया कि जिले में श्रीगुहान गौठान, करामज़ड़, नवागाव भावगीर, लूलेगोन्दी इत्यादि गौठानों में भी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा मल्टी-एक्टिविटी गतिविधियों से रोजगार और आमदनी प्राप्त कर अपनी आजीविका चला रही है, जिससे उनके सामाजिक व आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है।

विशेष लेख

नरवा विकास योजना से वन क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण के बड़े तादाद में हो रहे कार्य

कैम्पा मद से वर्ष 2019-20 के अंतर्गत 12 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर

संरचनाओं से 4.65 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का मिलेगा लाभ

राज्य शासन की महत्वाकांक्षी 'नरवा विकास योजना' के तहत प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थित नालों में कैम्पा मद की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 के तहत 12 लाख 9 हजार 485 संरचनाओं का निर्माण जारी है। इनमें से अब तक लगभग 11 लाख संरचनाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इनका निर्माण 155 करोड़ रूपए की राशि से किया जा रहा है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में इसके तहत 155 करोड़ रूपए की राशि से 01 हजार 766 किलोमीटर लंबाई के विभिन्न नालों में भू-जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इन संरचनाओं के पूर्ण होने पर 4 लाख 65 हजार 172 हेक्टेयर भूमि उपचारित होगी। इसमें वन क्षेत्रों के नालों में भू-जल संरक्षण कायज़ के लिए लूज बोल्डर चेकडेम, बोल्डर चेकडेम, ब्रशवुड चेकडेम, कंटूर ट्रेंच, परकोलेशन टैंक, अर्दन डेम, चेकडेम, एनीकट, स्टापडेम तथा गेबियन आदि संरचनाओं का काफी तादाद में निर्माण किया जा रहा है। इससे एक ओर वन भूमि के क्षरण को रोका जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर जल भंडार में वृद्धि की जा सकेगी। वन क्षेत्रों में जल भंडार की पर्याप्त उपलब्धता से वन्य जीवों को उनके रहवास क्षेत्र में ही चारा-पानी उपलब्ध होगा, जिससे वे आबादी क्षेत्रों की ओर आकर्षित नहीं होंगे। इसके साथ ही वनों के आसपास के ग्रामीणों तथा कृषकों को पेयजल तथा सिंचाई के साधन विकसित करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्ही.श्रीनिवास राव ने बताया कि कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 के तहत राज्य के वन क्षेत्रों में स्थित नालों में निर्माणाधीन 12.09 लाख संरचनाओं में से अब तक स्टॉपडेम, कंटूर ट्रेन्च, बी.जी.पी. तथा वाटरहोल्स निर्माण के कार्य को लगभग पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से अब तक दुर्ग वनवृत्त के अंतर्गत 79 हजार 206 संरचनाओं में से 69 हजार 278 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इसी तरह बिलासपुर वनवृत्त के अंतगज़्त 6 लाख 68 हजार 164 संरचनाओं में से 6 लाख 5 हजार 759, रायपुर वनवृत्त के अंतगज़्त 56 हजार 529 संरचनाओं में से 41 हजार 564 तथा जगदलपुर वनवृत्त के अंतर्गत 2 लाख 78 हजार सरंचनाओं में से 2 लाख 12 हजार संरचनाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा सरगुजा वनवृत्त के अंतर्गत एक लाख 17 हजार 129 संरचनाओं में से एक लाख 17 हजार 106 तथा कांकेर वनवृत्त के अंतर्गत 2 हजार 626 संरचनाओं में से 2 हजार 443 और वन्यप्राणी क्षेत्र के अंतर्गत 7 हजार 737 संरचनाओं में 6 हजार 840 संरचनाओं का का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

सीजी टीका एप ठप

छग स्वास्थ्य विभाग ने चिप्स को लिखा पत्र, कहा- शिकायतों की भरमार, निराकरण शून्य, जल्द ठीक करें व्यवस्थाएं

छत्तीसगढ़ में कोरोना को मात देने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने सीजी टीका एप लॉन्च किया था, ताकि वैक्सीनेशन में तेजी आए और प्रदेश कोरोना से जंग जीत सके, लेकिन साफ्टवेयर कंपनी सीजी टीका एप को सही ढंग से संचालित नहीं कर सकी। एप चलते-चलते ठप पड़ गया. ऐसे में टीकाकरण में ब्रेक लग गया है. चिप्स की नाकामी की वजह से टीकाकरण अभियान को तगड़ा झटका लगा है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने चिप्स मुख्य कार्यपालन अधिकारी पत्र लिखा है।

चिप्स को लिखा पत्र : स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि चिप्स द्वारा बनाया गया सीजी टीका पोर्टल ठीक प्रकार से नहीं चलने की शिकायतें लगातार सभी जिलों से मिल रही है. इससे भी बुरी बात यह है कि चिप्स में इन समस्याओं के संबंध में कोई अधिकारी बात तक करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में सभी जिलों को फिलहाल सीजी टीका पोर्टल के ठीक होने तक मैनुअल टीकाकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीजी टीका एप ठप : स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आपसे अनुरोध है कि पोर्टल के संबंध में सर्वर, बैंडविथ और अन्य समस्याओं का हल तत्काल करें. आपसे यह भी अनुरोध है कि चिप्स में एक टीम के 24×7 बैठने की व्यवस्था हो, जिससे जिलों की समस्याओं को सुना और समझा जा सके। उनका हल भी तत्काल निकाला जा सके।

पिछले 2 दिनों से आपको बार-बार बताया गया है कि सवज़र की समस्या आ रही है। बेहतर होगा कि आप इस प्रोजेक्ट को चिप्स से एस डीसी के सर्वर पर भी रेपलीकेट करके रखें, जिससे सर्वर की समस्या न आए, लेकिन चिप्स द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस विभाग के अनुरोध के बाद भी चिप्स से 24×7 हेल्प डेस्क भी नहीं बनाया. इन सभी व्यवस्थाओं को तत्काल ठीक करें।

CG TEEKA

मंत्री टीएस सिंहदेव बोले- App अभी बच्चा है जल्दबाजी में किया गया लांच

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई सरकारी वेबसाइट CG Teeka पूरी तरह से ठप हो गई है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैक्सीन की कमी और CG TEEKA App को लेकर बयान दिया है कि- 'App अभी बच्चा है, App जल्दी में बना है इसलिए हो रही हैं गड़बड़ियां। App को जल्दबाजी में लांच किया गया है। यदि कोई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं तो उसे जल्द ही ठीक करने की कोशिश की जाएगी। बच्चा चलना शुरू कर रहा है थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी ही।'

गौरतलब है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए राज्य सरकार ने अलग से पोटज़्ल बनाया है। यह केंद्र सरकार के Cowin portal से अलग है। यह ऑनलाइन पंजीयन का सिस्टम है। तय हुआ था CG Teeka पोर्टल में पंजीयन करवाने वालों को ही वैक्सीन की डोज लगायी जाएगी।

महामारी से निपटने के लिए केंद्र से मिल रही मदद, आठ दिन में 14 बार पहुंची राहत सामग्री : इसमें पिछले कई दिनों से दिक्कतें आ रही थीं। आज तो वह वेबसाइट की ठप्प हो गई। टीकाकरण केंद्रों पर बवाल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग ने वेबसाइट का संचालन करने वाली छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (Chips) पर ठीकरा फोड़ा है।

उप सचिव सुरेंद्र सिंह वाघे ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र भेजकर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने लिखा कि CG Teeka पोर्टल ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसकी शिकायतें सभी जिलों से आ रही हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि इन समस्याओं पर बात करने के लिए चिप्स का कोई अधिकारी भी उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि- पिछले दो दिनों से आपको बार-बार कहा जा रहा है कि सर्वर की समस्या आ रही है। बेहतर होगा कि इस प्रोजेक्ट को चिप्स से एसडीसी के सर्वर पर रेप्लिकेट करके रखें, लेकिन खेद का विषय है कि चिप्स ने इस सबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। स्वास्थ्य विभाग के अनुरोध के बाद भी 24 घंटा और सातों दिन काम करने वाला हेल्पडेस्क भी नहीं बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने चिप्स से सभी समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया है।

रायपुर पहुंचे 6 लाख 44 हजार डोज: 2 लाख 97 हजार युवाओं को लगेगा मंगल टीका, 45+ एज ग्रुप के 3 लाख 47 हजार लोगों को भी वैक्सीन लगेगी; इस महीने 3.70 लाख डोज और मिलेंगी

छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन की किल्लत कुछ हद तक दूर होने के आसार बन रहे हैं। कंपनियों ने जो शेड्यूल भेजा है, उसके मुताबिक मई महीने में प्रदेश को टीके की 12 लाख से अधिक डोज मिलनी है। आज उसमें से कोवीशील्ड वैक्सीन के 2 लाख 97 हजार 110 डोज पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे बेहद छोटा बताया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आज 18 से 45 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए कोवीशील्ड वैक्सीन की 2,97,110 डोज की एक छोटी आपूर्ति प्राप्त हुई है। इस आयु वर्ग के लिए हमारे टीकाकरण की वर्तमान दर के हिसाब से यह टीके अधिकतम 2 दिनों तक चल पाएंगे। सिंहदेव ने कहा, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपने लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाने और सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए टीकों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होगी। हम जितनी जल्दी सभी के लिए टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेंगे, हम धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ सकेंगे।

राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने बताया, नियमित उड़ान से कोवीशील्ड वैक्सीन का 6 लाख 44 हजार 410 डोज पहुंचा है। इनमें से 2 लाख 97 हजार 110 डोज 18 + के टीकाकरण के लिए होगा। शेष 3 लाख 47 हजार 300 डोज वैक्सीन 45 वर्ष से अधिक के लोगों के केंद्र प्रायोजित टीकाकरण में इस्तेमाल होगा। हवाई अड्डे से राज्य वैक्सीन भंडार लाने के बाद इन टीकों को जिलों में भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

ऐसा है वैक्सीन पहुंचने का शेड्यूल-अधिकारियों ने बताया, भारत बायोटेक ने जो शेड्यूल भेजा है उसके मुताबिक मई में उनको 3 लाख डोज वैक्सीन भेजनी है। अभी तक उनके कोवैक्सिन की केवल 1 लाख 3 हजार डोज ही मिल पाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी 9 लाख डोज भेजने की बात की है। इसमें से आज की खेप मिलाकर करीब 7 लाख डोज पहुंच गई है।

टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ेगी : बताया जा रहा है, आज वैक्सीन की खेप पहुंच जाने के बाद 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी प्रदेश भर में करीब 650-55 केंद्रों पर यह टीका लगाया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 700 से अधिक किया जाएगा। कल रात तक 18 से 44 आयु वर्ग के 3 लाख 99 हजार 262 लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका था।

अधिकांश केंद्रों पर प्रभावित रहा था टीकाकरण : टीके की कमी की वजह से अधिकतर शहरी टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाने का काम प्रभावित हुआ था। रायपुर, भिलाई जैसे शहरों में गरीबी रेखा से ऊपर और फ्रंटलाइन वर्कर श्रेणी के लोगों का टीकाकरण बंद हो गया था। फिर भी प्रदेश में कल 28 हजार 746 टीके लगाए गए।

रायपुर के कई टीकाकरण केंद्रों पर ऐसी नोटिस लगाई गई थी। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर और APL वर्ग का टीका उपलब्ध नहीं होने की बात थी।

चार वर्गों को अलग-अलग अनुपात में लग रहा है टीका : छत्तीसगढ़ में टीकाकरण चार अलग-अलग वर्गों में अनुपात के मुताबिक हो रहा है। किसी केंद्र पर मौजूद टीके का 16 प्रतिशत अन्त्योदय राशनकार्ड धारी को लगाना है। इस वर्ग में कल तक 76 हजार 941 लोगों को टीका लगा चुका था। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को 52 प्रतिशत टीका लगना था।

इस वर्ग के 1 लाख 68 हजार 774 लोगों को टीका लग चुका है। टीके का 20 प्रतिशत हिस्सा फ्रंटलाइन वर्कर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को आवंटित है। इस वर्ग के 45 हजार 611 लोगों को कल तक टीका लग चुका था। वहीं गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों को कुल टीके का 12 प्रतिशत हिस्सा मिलना है। अभी तक इस वर्ग में 1 लाख 7 हजार 936 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।

अमिताभ बच्चन ने सुनाई 'होप' पर एक कविता

हम लड़ेगें, साथ आएंगें और जीतेंगे - अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के बीच 'होप' के बारे में एक मेसेज शेयर किया। उन्होंने सभी से भारत के लिए एक साथ खड़े होने और वायरस से लड़ने की अपील भी की। बिग बी ने वीडियो में, 'होप' पर एक कविता सुनाई।

होप पर सुनाई बिग बी ने कविता : बिग बी ने कहा, होप कोई स्ट्रेटजी नहीं है। लेखक यह कहना चाहता है कि शब्दों से ज्यादा काम करना माइने रखता है। हां, यहां पर कुछ निश्चित तर्क नहीं है लेकिन, जैसा कि कई बुद्धिमान संतों का कहना है कि आशा एक शुरुआत नहीं है, इसे कभी-कभी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है और हम होप का सही मतलब भूल जाते हैं। हां, होप अकेले एक स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन जब होप हमारे कार्यों को दिशा देती है तो बड़ी चीजें भी संभव हो जाती हैं।

फ्रंटलाइन वर्कर्स-कोविड वॉरियर्स का स्वार्थहीन सबूत देखने को मिला : बिग बी ने आगे कहा, हर दिन हम कहानियां सुनते हैं कि लोग साथ आकर एक-दूसरे की मद्द कर रहे हैं। हर दिन हमें लोगों के निडर साहस, फ्रंटलाइ वर्कर्स और कोविड वॉरियर्स का स्वार्थ हीन सबूत देखने को मिलता है। हर दिन अंधेरा रोशनी में बदलता है क्योंकि लोग साथ आना और साथ खड़े होना चुनते हैं। बिग बी ने पोस्ट को कैप्शन में लिखा, ''हम लड़ेगें, साथ आएंगें और जीतेंगे!''

महामारी से निपटने अमिताभ ने दिया 15 करोड़ का योगदान, कोरोना के चलते अनाथ हुए 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी ली : महानायक अमिताभ बच्चन की मानें तो कोरोना महामारी के बीच पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। उन्होंने सोमवार रात अपने ब्लॉग में इस रकम का खुलासा उन ट्रोल्स को जवाब देने के लिए किया, जो लगातार उन पर महामारी में किसी तरह की मदद न करने का आरोप लगा रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं।

लोगों को सिर्फ 2 करोड़ के बारे में बताया: अमिताभ : बिग बी ने ब्लॉग में लिखा है, इस लड़ाई में कईयों ने योगदान दिया है और लगातार कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ उन 2 करोड़ रुपए के बारे में पता है, जो मैंने दिल्ली के एक कोविड केयर सेंटर को दिए हैं। लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजरते जाएंगे, मेरा योगदान लगभग 15 करोड़ रुपए होगा। सोमवार को चर्चा थी कि बिग बी ने दिल्ली के गुरु तेगबहादुर कोविड केयर सेंटर को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। बिग बी आगे लिखते

हैं, जाहिरतौर पर इस तरह के आंकड़े मेरे लिए मायने नहीं रखते। बल्कि मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं और अपनी कमाई उन लोगों पर खर्च करने का संकल्प लेता हूं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और सर्वशक्तिमान की कृपा से मैं यह राशि देने में सक्षम हूं। ऐसे समय में मुझे अपने पर्सनल फंड से कुछ और खर्च करना पड़े तो मुझे योगदान देने में झिझक नहीं होगी।

बिग बी ने अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी भी ली : बिग बी ने अपने ब्लॉग में बताया है कि उन्होंने ऐसे दो बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला भी लिया है, जिन्होंने कोविड के कारण अपने पैरेंट्स को खो दिया है। उनके मुताबिक, इन बच्चों को हैदराबाद के अनाथालय में रखा जाएगा और उनकी पहली से लेकर दसवीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्च वे उठाएंगे। इतना ही नहीं, अगर दसवीं पूरी होने के बाद ये बच्चे प्रतिभाशाली निकलते हैं तो उनकी उच्चा शिक्षा का खर्च भी इन्हीं कंडीशंस के तहत उठाया जाएगा। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में उनके द्वारा की गई चैरिटी की लिस्ट भी साझा की है।

भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने रचाई शादी

दुल्हन की सुंदरता के आगे एक्ट्रेस भी है पानी कम भोजपुरी एक्टर रीतेश ने अपनी शादी की फोटोज इंस्टग्राम पर शेयर की हैं। फोटो शेयर करते हुए रीतेश पांडे ने सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों से अपनी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद मांगा है। भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने रचाई भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार एक्टर रितेश पांडे की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। रितेश अबतक बहुत सी हिट फिल्में दे चुके है। पिछले कुछ दिनो में रितेश पांडे अपनी सगाई को लेकर चर्चित रहे हैं। हाल ही में उनकी सगाई की तस्वीरें सामने आयी थी। जिसके बाद लोगो को लगा कि रीतेश की सगाई की ये फोटो फेक हैं। लेकिन ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं थी उन्होंने अब सच में शादी भी कर ली है। एक्टर ने 14 मई को सात फेरे लिए है। रितेश अपने जन्मदिन के दिन ही शादी के पवित्र बंधन में बंध गए है। तो अब एक्टर की शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रितेश पांडे ने कल को वैशाली पांडे संग सात फेरे लेते हुए जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा कर लिया हैं। एक्टर की शादी

अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई है। रितेश ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर दी है। शादी के बाद रितेश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी शादी की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। रीतेश ने पत्नी के साथ की फोटोज शेयर करते हुए लिखा है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ,आप सभी के आशीर्वाद की अभिलाषा है। रीतेश की यह फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

गर्मी के इस मौसम में मुल्तानी मिट्टी से पा सकते हैं चमकदार त्वचा, ऐसे करें इस्तेमाल

कुछ साल पहले तक मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल महिलाएं बड़े पैमाने पर अपना सौंदर्य निखारने के लिए करती थीं। फिर रेडीमेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भरमार ने मुल्तानी मिट्टी की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया था।

मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल ब्यूटी मैटीरियल है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। आप भी इसका इस्तेमाल अपनी त्वचा को निखारने के साथ ही कई समस्याओं से राहत पाने के लिए कर सकती हैं। जानिए, मुल्तानी मिट्टी के फायदों के बारे में।

अब से कुछ साल पहले तक मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल महिलाएं बड़े पैमाने पर अपना सौंदर्य निखारने के लिए करती थीं। फिर रेडीमेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भरमार ने मुल्तानी मिट्टी की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया था। लेकिन केमिकल बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स ने एक बार फिर से मुल्तानी मिट्टी की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया है। ऐसा हो भी क्यों न, इसमें चेहरे ही नहीं पूरे शरीर को निखारने की नेचुरल क्वालिटी होती है। गर्म मौसम में भी आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल अपनी सुंदरता बढ़ाने, स्किन को चमकदार, मुलायम बनाने के लिए कर सकती हैं। लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले, सही तरीका अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से जरूर जान लें।

स्किन बनती है चमकदार अगर साबुन के रोजाना इस्तेमाल से आपकी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है तो मुल्तानी मिट्टी को चंदन पावडर और गुलाबजल में मिलाकर पेस्ट बना लें। नहाने से तकरीबन आधा घंटा पहले इसे पूरे शरीर पर लेप की तरह लगा लें, कुछ ही दिनों में त्वचा खिली-खिली और चमकदार नजर आएगी।

हट जाती है डेड स्किन नहाते समय रोजाना अगर मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट को पूरे शरीर पर साबुन की तरह इस्तेमाल किया जाए तो रूखी बेजान त्वचा से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही डेड स्किन भी आसानी से हट जाती है, जिससे रोमछिद्र बंद नहीं होते और त्वचा में ताजी सांस आने-जाने से कई तरह के इंफेक्शन के खतरे कम हो जाते हैं।

झुर्रियां होती हैं कम : ढीली पड़ती चेहरे की त्वचा के लिए या झुर्रियों से बचने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी का पैक बहुत ही लाभदायक होता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि झुर्रियों की वजह से ही आप समय से पहले ओवरएज नजर आने लगती हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए रोजाना मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें।

घमौरियों से निजात गर्मी के दिनों में घमौरियों की समस्या होना कॉमन है। इस समस्या से भी मुल्तानी मिट्टी निजात दिलाती है। इसके लिए मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट में नीम की पत्तियां पीसकर मिला लें और लेप बनाकर जहां घमौरियां हैं, लगा लें। इससे तुरंत राहत मिलती है। यही नहीं इस लेप के लगाने से घमौरियां अपने काले दिखने वाले निशान भी नहीं छोड़ पाती हैं। बालों के लिए उपयोगी मुल्तानी मिट्टी चेहरे की ही तरह बालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। मुल्तानी मिट्टी के पावडर को अगर छाछ में भिगोकर इससे सिर धोएं तो बालों में होने वाली रूसी की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही बाल गिरने भी बंद हो जाते हैं।

कोरोना से जंग समझदारी के संग

याद रखें

- किसी Covid-19 पॉज़िटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने पर तत्काल जांच न कराएं, लक्षण आने पर अथवा 5-7 दिन उपरांत ही जांच करवाएं
- कोरोना का बुखार 10 से 12 दिन तक रह सकता है, यह CT स्कैन कराने का सही मापदंड नहीं है
- अस्पताल में तभी भर्ती होना चाहिए जब मरीज की ऑक्सीजन की सांद्रता (सेचुरेशन) 93 से कम हो
- जिन मरीजों का इलाज घर पर चल रहा हो, वो खून पतला करने वाली दवाई न खाएं
- संक्रमण के पहले सप्ताह में स्टेरॉयड न लें, इससे संक्रमण और गंभीर हो सकता है
- रेमडेसीवीर व टॉसीलीजुमाब लगाने के खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं, इसे डॉक्टर की सलाह पर और गंभीर रोगियों को ही दिया जाना चाहिए

श्री भूपेश बघेल
मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

कोरोना से डरना मत
मास्क लगाना भूलना मत

मास्क ठीक ढंग से पहनें

हाथों को नियमित रूप से धोएं

आपस में 6 फीट की दूरी बनाएं

छत्तीसगढ़ संवाद–11514/88